हाईकोर्ट ने खनिज अधिकारियों पर लोकायुक्त में एफआईआर कराने के दिए आदेश

- याचिकाकर्ताओं पर लगाई 50 - 50 हजार की कास्ट
- मामला खनिज विभाग द्वारा खदान आवंटन का

नव भारत न्यूज

इंदौर. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आज खनिज अधिकारियों पर लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए है. हाईकोर्ट ने साथ ही टिप्पणी की है कि बिना खनिज अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह के कृत्य नहीं हो सकते है.

आज इंदौर हाईकोर्ट के जस्टिस विनय रूसिया और बिनोद कुमार द्विवेदी ने खदान आवंटन में फैसला सुनाते हुए कहा कि गैर कानूनी तरीके से खदान का लीज आवंटन, नवीनीकरण और विक्रय पूर्णत: अधिकारियों के सांठगांठ के बिना संभव नहीं है. ऐसे कृत्य के लिए भ्रष्टाचार नियम के तहत अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाए. दरसासल मामला देपालपुर तहसील के रावद गांव के खसरे नंबर 33/1/4/3 और 33/1/4/4 पर स्थित खदान का लीज आवंटन किया गया था. उक्त खदान दीपक

वर्मा को 1987 में खदान आवंटित की गई थी. उसके बाद 1998 में लीज नवीनीकरण और 2008 में सना खान को विक्रय कर दी गई. उक्त मामले में 33/1/4/3 खसरे की खदान 3.6 हैक्टेयर में आवंटित की थी. सना खान ने दीपक वर्मा के दूसरे खसरे 33/1/4/4 में भी अवैध खनन कर लिया. इस मामले का अपर कलेक्टर गौरव बैनल को शिकायत की गई. बैनाल ने जांच करने आदेश दिए. जांच में सना खान ने 3.6 के जगह 5 हैक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर खनन कर शासन को राजस्व का नुकसान पहुंचाया. खनिज प्रभारी अपर कलेक्टर ने सना खान पर अवैध खनन और विक्रय को लेकर 29 करोड़ रुपए वसूली करने का प्रकरण बनाया. उक्त मामले में दोनों एक दूसरे की हाईकोर्ट में शिकायत कर याचिका लगाते रहे है. आज ही हाईकोर्ट डबल बेंच के जस्टिस विवेक रुसिया और विनय कुमार द्विवेदी ने फैसला सुनाते हुए खनिज अधिकारी पर लोकायुक्त में एफआईआर दर्ज करने और याचिकर्ताओं पर न्यायालय का समय बर्बाद करने को लेकर 50-50 हजार के कास्ट लगाई.

खनिज अधिकारियों का कारनामा

तत्कालीन अधिकारियों ने 1987 में जब खदान आवंटन की थी, उस दीपक वर्मा की उम्र 7 वर्ष बताई जा रही है. उनका जन्म 1980 में होना पाया गया है. एक बच्चे केडी एनएसएम से खदान आवंटन हो गई और कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों को मालूम हो नहीं चला? यह अधिकारियों के बिना असंभव है, इसलिए कोर्ट में लोकायुक्त को एफआईआर करने के निर्देश दिए है.

उज्जैन के प्रसिद्ध विक्रम उत्सव ने जीता वॉव अवार्ड एशिया 2025

एशिया के शासकीय समारोह की विशेष श्रेणी में गोल्ड अवॉर्ड का मिला सम्मान

- वॉव अवार्ड एशिया की टीम भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को देगी अवॉर्ड
- 18 साल पूर्व डॉ मोहन यादव ने किया था विक्रम उत्सव प्रारंभ

नवभारत न्यूज

उज्जैन, विक्रम उत्सव के आयोजन को वॉव अवार्ड एशिया का सम्मान प्राप्त हुआ है. मुंबई में हुए एक आयोजन में इसकी घोषणा की गई. अब जल्द ही वॉव अवार्ड की टीम भोपाल पहुंचेगी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को सम्मानित करेगी.

नवभारत से चर्चा में विक्रमादित्य शोधपीठ के निर्देशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा आयोजित विक्रमोत्सव 2025 को वॉव अवॉर्ड एशिया 2025 द्वारा एशिया के शासकीय समारोह की विशेष श्रेणी में गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

भोपाल में होगा समारोह

विक्रम उत्सव के जिस प्रकार से यह सम्मान प्राप्त हुआ है,ऐसे में एक

(26 फरवरी 2025 को उज्जैन में विक्रम उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किया था केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत उपस्थित रहे(फाइल फोटो)

समारोह भोपाल में आयोजित होगा, जिसमें वॉव अवार्ड एशिया की टीम भोपाल आएगी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को यह अवॉर्ड प्रदान करेंगी. इससे पहले भी विक्रमोत्सव 2024 को एशिया का बिगेस्ट रिलीजियस अवॉर्ड मिल चुका है.

मुख्यमंत्री डॉ यादव का समर्पण भाव

विक्रमोत्सव 2025 को यह सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार एवं महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने इसे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की संस्कृति और विरासत के प्रति उनके समर्पण का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि विक्रमोत्सव 2025 को प्राप्त यह सम्मान न केवल मध्य प्रदेश बल्कि समस्त भारत वर्ष के लिए गौरव का विषय है. विक्रमोत्सव एक आयोजन मात्र नहीं है बल्कि इन सबसे बढ़कर संस्कृति, विरासत और विकास का बेजोड़ संगम हैं.

300 से अधिक गतिविधियां हुई

विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि विक्रमोत्सव 2025 अंतर्गत 300 से अधिक विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां सम्पन्न हुई. इस महोत्सव में लाखों लोग भागीदार रहे जबकि सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग विक्रमोत्सव से जुड़े.

18 वर्ष पूर्व का पौधा आज लहलहा रहा

नवभारत को मिली जानकारी के अनुसार 18 साल पहले अपने कुछ करीबी मित्रों, परिचितों स्नेहीजनों के साथ मिलकर विक्रम उत्सव की शुरुआत रामघाट पर की थी. धीरे-धीरे यह शहर के अन्य स्थानों पर आयोजित किया जाने लगा. इसमें लाइट एंड साउंड शो भी बाद में जोड़ा गया और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही, जिसमें धार्मिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होने लगी और देश के नाम की हस्तियां इसमें शामिल होती रही. 18 साल पहले जो नन्हा सा पौधा मोहन यादव द्वारा आरोपित किया गया था वह आज देशभर में लहलहाने लगा है.

मंत्रालय के गलियारों से

कन्हैया लोधी

दो ताकतवर अफसरों में दबदबे का द्वंद

मंत्रालय में दो ताकतवर अफसरों के बीच दबदबे का द्वंद शुरू हो गया है. दोनों ही अधिकारी एक-दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं. पहले तो इसे लेकर केवल कहासुनी तक ही मामला सीमित था, लेकिन अब दबीं जुबां अफसर भी चर्चा करने लगे हैं. अफसर भी अब इस पॉवर गेम की थाह लेने में लगे हैं कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा. अफसरों का उलझन ये है कि आखिर वे ट्यूनिंग बिठाएं तो किससे बिठाएं. क्योंकि दोनों में से किसी एक भी नाराज करना यानी अपनी सीआर को दांव पर लगाने जैसा होगा, ऐसे में वे कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है. और अभी तेल देखो और तेल की धार देखो, वाली स्थिति में है. अब देखना ये है कि इन दो ताकतवर अफसरों में दबदबे का द्वंद आखिर क्या असर दिखाता है.

अब नये सिरे से बांडिंग की कवायद

भाजपा को आखिरकार नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है. नये प्रदेश अध्यक्ष बनते ही अब भाजपा के विधायकों और पार्टी से जुड़े नेताओं के सामने नये सिरे से बांडिंग की चुनौती आ खड़ी हुई है. अब वे संगठन के मुखिया के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष के विधायक होने का फायदा दूसरे विधायकों को स्वाभाविक रूप से मिलेगा और शायद मिलना भी शुरु हो गया है. जिस दिन नामांकन होना था, उसी दिन बड़ी संख्या में भाजपा विधायकों ने भी प्रदेश कार्यालय में डेरा डाल रखा था, जितनी बैचेनी नाम को लेकर दूसरे पदाधिकारियों में थी, उससे कम बैचेनी विधायकों को नहीं थी. जब नाम को लेकर तस्वीर साफ होने लगी, तो कई विधायक, पदाधिकारियों के चेहरे पर राहत को साफ पढ़ा जा सकता था.

इंतहा हो गई, इंतजार की

लगभग दो माह पहले ही ये तय हो गया था कि एक प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी की मंत्रालय में वापसी होगी. लेकिन प्रशासनिक आर्डर नहीं निकल पा रहा था, अब की तब वाली स्थिति लगातार बनी हुई थी. ऐसे मौके शायद कम ही होते हैं कि जब ये तय हो जाये कि उनके स्थान पर किसे पदस्थ किया जाएगा, उसके बाद भी उनको पुरानी जिम्मेदारी ने मुक्त न किया जाए. अब साहब कर भी क्या सकते थे, सिवाय इंतजार के, आखिरकार सरकार ने लंबे इंतजार के बाद उनकी सुध ली. जैसे ह आर्डर निकला तो पहले हॉफ में रिलीव हो गये और दूसरे हॉफ में नई जगह ज्वाइनिंग भी दे दी.

चेहरा जिसे सबने पढ़ा

कहते हैं न कि चेहरा सब बयां कर देता है. एक चेहरा जो कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन के दिन नजर नहीं आया, अगले दिन विधिवत घोषणा के दिन जरुर नजर आया. बेहद कद्दावर नेताजी जब नये प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए मंच पर पहुंचें तो उनका चेहरा देखने लायक था, उनके चेहरे पर उभरे दर्द को कोई भी सहज रूप से पढ़ सकता था. आखिर दर्द उभरा तो उसका कारण भी है, साहब एक तो सरकार से बाहर अभी बिना पॉवर हैं, दूसरा वे अध्यक्ष के दावेदार भी थे, तो फिर ये दर्द तो स्वाभाविक और सहज था ही, आखिर इंसान तो इंसान ही है.

ग्वालियर-चंबल बनेगा विकास का नया केंद्र

सीएम यादव बोले-अब बीहड़ की बिजली से जगमगाएंगे मप्र और उप्र

ग्वालियर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए संकल्पित है. हम सबके जीवन में उजाला लाने के लिए कटिबद्ध हैं. ग्वालियर-चंबल क्षेत्र शीघ्र ही राज्य का सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा.

मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय किसानों से अपील की कि वे अपनी जमीन बेचने की कतई न सोंचे, क्योंकि इस क्षेत्र में शीघ्र ही रोजगार के नए अवसर और विकास की नई धाराएं बहने वाली हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को ग्वालियर के आईएसबीटी परिसर में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां 265.56 करोड़ रुपये की लागत

वाले विभिन्न विकास कार्यों का रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया. इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत पांच पात्र हितग्राहियों को मंच से हितलाभ भी वितरित किए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में नदियों को जोड़ने का अभियान चल रहा है. केंद्र सरकार की मदद से यहां पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना पर करीब 70,000 करोड़ रुपये की लागत से काम किया जा रहा है. साथ ही केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना से भी ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के किसानों को व्यापक

> मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के बीहड़ों को अब बेहतर तरीके से विकसित किया जा रहा है. यहां के बीहड़ों में जल्द ही केंद्र सरकार के सहयोग से 2000 मेगावाट क्षमता का एक बड़ा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है. यह मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की संयुक्त परियोजना होगी. इस परियोजना से दोनों ही प्रदेशों को ऊर्जा आपूर्ति होगी. मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश 6-6 माह बराबरी से इस परियोजना से उत्पादित बिजली का उपभोग करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि आगरा से ग्वालियर के बीच बन रहे नये सिक्स-लेन नेशनल हाई-वे के चलते बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने इस क्षेत्र में बड़ा निवेश करने में अपनी रुचि दिखाई है.

स्तर पर लाभ मिलने वाला है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व पटल पर भारत के गौरव को प्रतिस्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुर्सी संभालने के बाद दिन-रात एक कर प्रदेश की 9 करोड़ जनता के लिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की है. हमारी मांग थी कि ग्वालियर-चंबल संभाग में डॉ. अंबेडकर धाम की स्थापना हो, जो बाबा साहेब की विचारधारा का मंथन केंद्र बने. उन्होंने बताया कि ग्वालियर जिले के डबरा के जौरासी गांव में 8 करोड़ रुपए की लागत से डॉ. अंबेडकर धाम बन रहा है.

> सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है. वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि आज ग्वालियर के लिए गौरवशाली दिन है. उन्होंने कहा कि ग्वालियर के हजीरा अस्पताल को पहला स्थान मिला है. इसे जिला अस्पताल के समकक्ष बनाया जाए. उन्होंने कहा कि ग्वालियर में अब मरीजों की बायपास सर्जरी की व्यवस्था भी की जाए. ग्वालियर में बड़े उद्योग धंधों की स्थापना की जाए. कार्यक्रम के अंत में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने सभी का आभार व्यक्त किया.

जबलपुर, डिंडौरी में मूसलाधार बारिश

40 किमी की रफ्तार से चलेगी हवा

09 जुलाई तक प्रदेश में बारिश के आसार

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 5 जुलाई. मप्र के डिंडौरी, जबलपुर, सिवनी, मंडला, दमोह सहित जिलों में रविवार को मूसलाधार बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग ने यहां भारी बारिश की संभावना को देखते हुए आरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही ग्वालियर, दतिया, श्योर पुरकलां, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, विदिशा, राजगढ़, कटनी, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में भी अति बारिश हो सकती है. इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, सीधी, रीवा, सिंगरौली सहित जिलों में

> मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी भाग तथा उससे संलग्न पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. संबंधित चक्रवाती परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 7 .6 किमी ऊपर तक फैला हुआ है. अगले 2 दिनों के दौरान इसके उत्तर ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है.

गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. प्रदेशभर के जिलों में अति बारिश को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान लगाया है. इस दौरान करीब 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. प्रदेश में 9 जुलाई तक झमाझम बारिश की संभावना जताई है.

पेज एक का शेष

लीडरशिप की पाठशाला है समिति...

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि दुग्ध-उत्पादन, औद्योगिक विकास सहित अन्य क्षेत्रों में हो रहे नए कार्यों में सहकारी समितियों को प्राथमिकता मिलेगी. उन्होंने कहा कि सहकारिता समाज को एक करने के साथ ही युवाओं को बेरोजगारी से बचाने का माध्यम है. रोजगार का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है. युवाओं को स्वरोजगार और स्वावलंबन से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है और वर्ष 2025 को रोजगार एवं उद्योग वर्ष के रूप में मना रही है. सभी क्षेत्रों में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही सरकार: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवाओं के जीवन की असली परीक्षा कॉलेज की शिक्षा पूर्ण होने के बाद शुरू होती है। राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है. मप्र वन्य संपदा और जलराशियों से संपन्न है. प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार संकल्पित है. इसी उद्देश्य से अलग-अलग मंचों पर युवाओं से संवाद किए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में उन्हें भी नेतृत्व का अवसर मिले.

मढ़ई क्षेत्र में जिप्सी चलाने वाली संगीता का मंच से कराया परिचय: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में कई नवाचार हो रहे हैं। इसी के तहत को-ऑपरेटिव पब्लिक पार्टनरशिप सीपीपीपी के माध्यम से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सफारी चलाने के कार्य में भी महिलाओं की समिति सक्रिय है। उन्होंने मढ़ई क्षेत्र में जिप्सी चलाने वाली संगीता सोलंकी का मंच से परिचय कराया. संगीता ने बताया कि बाघ सहित कई वन्य प्राणियों से समृद्ध मढ़ई क्षेत्र में वे बिना डर के पर्यटकों को जंगल सफारी कराती हैं और प्रति माह लगभग 14 हजार रूपए की आय हो रही है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सहकारिता से उद्योग प्राप्त करने वाली 30 महिलाओं को सिलाई मशीन टूल किट वितरण के प्रतीक स्वरूप एक महिला को सिलाई किट प्रदान की.

पश्चिम रेलवे-अहमदाबाद मण्डल

शुद्धिपत्र-1

विषय : Sr/DSTE/Co/ADI अहमदाबाद मण्डल के क्षेत्राधिकार में विकास कार्यों के लिए परियोजना पर्यवेक्षण सेवाएँ प्रावधान के लिए प्रोजेक्ट सुपरविज़न सर्विसीस एजेंसी (PSSA) की नियुक्ति; संदर्भ : निविदा सुचना सं. DRM-SnT-ADI-Sig 16 of 2024-25. उपरोक्त विवरण निविदा दस्तावेज **DRM-SnT-ADI-Sig 16 of 2024-25** के लिए कृपया www.ireps.gov.in देखें। **(संख्या: SG. SG/W/722 (DRM-SnT-ADI-Sig 16 of 2024-25) दिनांक 04.07.2025)** ADI-100

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(Ordinary Original Civil Jurisdiction)
ARB. P. No. 957/2024

INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD. ....PETITIONER

Versus

BAVITA SINGH RATHORE AND ANR. ....RESPONDENTS

To,
RESPONDENT No.1:
BAVITA SINGH RATHORE
21/1, VAIBHAV NAGAR, SECTOR-A
KANADIA ROAD, INDORE-452016
MADHYA PRADESH
EMAIL: dharmendrasrathore@gmail.com

WHEREAS the above named **Petitioner has filed a petition under Section 11 (6)of the Arbitration & Conciliation Act, 1996. Whereas, this Court issued notice to you, the above named Respondent.**

AND

WHEREAS it has been shown to the satisfaction of the Court that it is not possible to serve you in the ordinary way, therefore, this notice is given by publication directing you to make appearance before Ld. Joint Registrar (Judicial) of this Hon'ble Court on **09.07.2025 at 11.00 A.M.,** to defend the above mentioned petition.

Take notice that in default of your appearance on the day mentioned above, the Petition will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court in terms of order dated **15th day of April, 2025.**

Assistant Registrar(O) for Registrar General

सफलता

विजयवर्गीय ने जनभागीदारी पर दिया जोर

राष्ट्रीय निकाय में मप्र 'मॉडल स्टेट'

- मानेसर में निकायों के अध्यक्षों का सम्मेलन
- मप्र से मंत्री कैलाश ने गिनाई प्रदेश की उपलब्धियां

भोपाल, 5 जुलाई. गुरुग्राम की पुण्यभूमि मानेसर में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश मॉडल स्टेट के रूप में उभर करके सामने आया. सम्मेलन के अंतिम दिन मध्य प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे.

यहां उन्होंने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2014 के बाद से शहरी स्थानीय निकाय के बजट में काफी वृद्धि हुई है. शहरी स्थानीय निकाय हमारे लोकतंत्र की नींव है. लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की जड़ें जितनी गहरी और स्थानीय स्तर पर सिंचित होंगी, हमारा राष्ट्र उतना ही सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेगा.

> मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहरी स्थानीय निकायों में जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है. इंदौर का उदाहरण को देते हुए जनभागीदारी के बारे में बताया. उन्होंने बीते समय की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक बार इंदौर नगर निगम में फंड की कमी हो गई थी. तब उन्होंने आमजन से सीमेंट के लिए बोला था. उस दौरान जनभागीदारी की पहल से उनके पास 80 करोड़ रुपये की सीमेंट इकट्ठा हुई थी. इसी सीमेंट से फिर सड़कों का निर्माण कराया गया. ये जन सहभागिता की सफलता का प्रमाण है. आज अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के पावन अवसर पर उन सभी सहकारी संस्थाओं को हार्दिक शुभकामनाएं, जो राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में भारत में सहकारिता एक नई ऊर्जा और विस्तार के साथ आगे बढ़ रही है. गांव-गांव में रोजगार, संसाधन और सहभागिता का सशक्त माध्यम बन चुकी सहकारिता, आज समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की नींव बन रही है.

डीएवीवी के पूर्व कुलपति प्रो. सिंह भी आरोपी

भोपाल. सीबीआई ने देशभर में मेडिकल कॉलेजों को फर्जी तरीके से मान्यता दिलाने के एक बड़े घोटाले का खुलासा किया है. सीबीआई ने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर के चेयरमैन सुरेश भदौरिया और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन एवं डीएवीवी के पूर्व कुलपति प्रो. डीपी सिंह को आरोपी बनाया है. इस मामले में रावतपुरा सरकार उर्फ रविशंकर महाराज समेत कुल 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के फर्जीवाड़े में सीबीआई का लगातार शिकंजा अब कसता जा रहा है. इस मामले में ग्वालियर-चंबल के प्रसिद्ध संत रावतपुरा सरकार उर्फ रविशंकर महाराज के साथ ही 35 नामजद के खिलाफ केस दर्ज है. इन सभी पर करेप्शन के आरोप हैं. मामले में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डीपी सिंह का नाम भी सामने आया है. इस कांड में वे भी आरोपी हैं. वर्तमान में वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के चांसलर हैं. अप्रैल 2024 में टाटा इंस्टीट्यूट में चांसलर बनने से पहले वह यूजीसी के चेयरमैन थे. इससे पहले वह इंदौर के देवी अहिल्या विवि के कुलपति थे. वे बीएचयू के भी कुलपति रह चुके हैं. उन पर आरोपी है कि रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज को एनएमसी की पॉजिटिव रिपोर्ट दिलवाने में उन्होंने भूमिका निभाई. सीबीआई पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7390/60